>

Title: Need to implement irrigation projects in Bihar.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति महोदय आपको धन्यवाद कि आपने मुझे एक लोकहित के मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है। मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि हमारे बिहार और झारखंड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। यह अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना है इसका नाम उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना है। मैं बताना चाहता हूं कि यह परियोजना वर्ष 1975 में शुरू हुई। इसकी प्रारंभिक लागत मात्र 30 करोड़ रुपये थी। अभी स्थिति यह है कि लगभग 750 करोड़ रुपये इस पर खर्च हो चुके हैं। प्रति वर्ष 12 करोड़ रुपये स्थापना व्यय पर खर्च हो रहे हैं। लेकिन अभी तक यह परियोजना अधूरी है। इस परियोजना से बिहार और झारखंड के तीन जिले, झारखंड का पलामू जिला, बिहार का मेरे संसदीय क्षेत्र का औरंगाबाद और गया जिला, दो राज्यों के तीन जिलों को मिलाकर एक लाख 24 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इससे 25 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा। स्थिति यह है कि इस परियोजना का जो आरसीसी वर्क है, जो पक्का काम है, वह लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन उसमें लोहे के जो स्लुइस गेट लगाने हैं, जिससे बांध में पानी जमा हो सके, उस पर भारत सरकार के वन पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 2007 में पाबंदी लगा दी। भारत सरकार के वन पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि बेतला नेशनल पार्क और टाइगर प्रोजैक्ट पर पानी के जमा होने से दुप्रभाव पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह परियोजना काफी लाभप्रद और महत्वपूर्ण है। इससे लगभग सवा लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होनी है। इसके मुख्य नहर का 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इसकी शाखा नहरें लगभग 50 प्रतिशत खुद चुकी हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इसका बैराज लगभग 98 प्रतिशत बनकर तैयार है। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि डैम में लोहे के फाटक के अभाव में पानी जमा नहीं हो रहा और यह नहर एकदम बरसाती नहर के रूप में है।

18.07 hrs.

(Dr. M. Thambidurai *in the Chair)*

जब कोयल नदी के कैचमैंट एरिया में बारिश होती है तो बैराज के माध्यम से उस पानी को नहर में मोड़ दिया जाता है। ...(व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा।...(व्यवधान) मैं बताना चाहता था कि इसके लिए 7 से 8 हजार हैक्टेयर जमीन किसानों से ले ली गई। उनकी जमीनें खोद दी गई, नहरों का निर्माण कर दिया गया, लेकिन उनमें पानी नहीं आता। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पूरा सौ प्रतिशत इलाका उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : What is your demand?

श्री सुशील कुमार सिंह : भारत सरकार एक तरफ कहती है कि हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनाना चाहते हैं। जब अनाज उत्पादित नहीं होगा तो यहां के नागरिकों को अनाज कहां से देंगे। क्या आयात करेंगे, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं? अगर यह परियोजना पूरी हो जाए तो इससे भूजल स्तर ऊपर उठेगा और पूरे इलाके में पेयजल की सुविधा बहाल हो सकती है।...(व्यवधान)

मेरी अंतिम बात सुन ली जाए।...(व्यवधान) इस परियोजना को पूरा होने में लगभग एक हजार करोड़ रुपये लगने हैं। एक हजार करोड़ रुपये लगाकर एक वर्ष में एक हजार करोड़ रुपये की खरीफ की फसल, धान और लगभग 500 करोड़ रुपये का गेहूं उत्पादित होगा। कोई ऐसी परियोजना नहीं है जिसमें इतने लोगों को रोजगार दिया जाए। उग्रवाद की समस्या का समाधान हो सके और एक साल में डेढ़ गुना मुनाफा रिकरिंग में हो। प्रति वर्ष 1500 करोड़ रुपये का अनाज उत्पादित होगा।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦ **